



आधुनिक समाचार नेटर्वक

आधुनिक समाचार

प्रयागराज से प्रकाशित एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रसारित

Download From



Adhunik Samachar



संक्षिप्त समाचार

ब्लू लाइन पर चोर काट ले गए, केबल, इस रुट पर बड़ी यात्रियों की मुश्किलें

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। राजेश व व कामल की शादी की बुधवार को 27 वीं सालगिरह थी। सालगिरह बनाने की तैयारियां हो रही थीं। पूरा परिवार रात को साल गिरह मनाने की तैयारी की बात कर सोचा था। मगर क्या पता था कि शादी को 27वीं सालगिरह का दिन उनका आखिरी दिन होगा।

दक्षिण दिल्ली के देवली गांव में बैठे अर्जुन (20) ने सेना से



सेवनिवृत्त पिता राजेश कुमार (51), मा कोमल (46) और बहन कविता (23) की बुधवार सुबह नशस्त हत्या कर दी। बुधवार को ही माता-पिता की 27वीं सालगिरह थी। डीयू से स्नातक कर रहे अर्जुन ने पिता के फैज गाले चाकू, (झार) से तीनों का गला रेत दिया। इसके बाद वह पुलिस व स्थानीय लोगों को गुमराह करने के लिए जिम लाल गया। जिम से लौटने के बाद पड़ोसियों को सुनाना दी। दक्षिण जिले के वाहन चोरी निर्वाचक दस्ते (एटीएस) ने सीसीटीवी कंपनी की फुटेज, घर से चोरी व लूपाट के स्क्रूत न मिलने और अर्जुन दिनभर की जाच के बाद शाम को उसे गिरफतार कर लिया।

दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान के अनुसार, मल्लिवासे में महेंद्रांग के खेड़ों गांव में निवासी पिता के सरेआम पीटने, डांटने व रोकतक से अपराधियों का

युक्त बता रही है।

आरोपी अकेला रहना चाहता था। पुलिस उसे साड़ों के किस्म का युक्त बता रही है।

दिल्ली में कानून व्यवस्था बदलता, राजधानी पर अपराधियों का कब्जा'

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। कुर्वत के विदेश मंत्री अबदुल्लाह अल याह्या भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर मालवार को भारत पहुंचे। जहां बुधवार को यहां ने पीएम मोदी और

उच्च टैरिफ की ट्रूप की घोषणा से भारत के लिए पैदा होंगे बड़े नियात अवसर, अमेरिकी व्यापार में गिरावट

(आधुनिक समाचार नेटर्वक)

नई दिल्ली। ट्रूप की घोषणा के बाद नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुम्मिलयमें को कहा, ट्रूप ने जो भी घोषणा होता है, मुझे लगता है कि वह भारत के लिए अवसर है। हम

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए नियात के बड़े अवसर पैदा होंगे।

घरेलू उद्योग को इस अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पिछले स्लिप में खड़े हैं

अब साल यह है कि अगर हम वास्तव में खुद को तैयार करते हैं, तो इससे नियात में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, क्योंकि व्यापार में बदलाव होने वाला है। एजेंसी सुम्मिलयमें की यह टिप्पणी इसलिए

से अधिक लाभ होता है। उन्होंने कहा, व्यापार सिर्फ नियात के बारे में न होकर आयात से भी जुड़ा है। बेरी ने कहा, हमारे पास एक अस्पृष्ट विनियम दर होने से संरचनात्मक रूप से हमारा व्यापार घाटा होगा।

हम निवेश करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास संरचनात्मक रूप से चालू खाता घाटा भी होगा। ये अच्छे हैं, बुरे नहीं। भारत को चीन लेस बन रणनीति को अपनाने में अब तक सीमित सफलता मिली है, जबकि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मल्यानिया को इसका फॉर्मैशन मिला है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्ता अम, सरल करना चाहिए। ट्रूप ने

पिछले स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के लिए अवसर को लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रूप ने

पहली स्लिप में खड़े हैं और गेंद हमारी तरफ आ रही है। हम इसे पकड़ेंगे या छोड़ देंगे, यह हमें देखना है। अमेरिका के नवनिवाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रूप की चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा से भारत के लिए अवसर हो जाएगी। एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़े अवसर पैदा होने के ल



प्रदेश आख/पास



भारत

वाराणसी, रायबरेली



वाराणसी

विश्व एड्स दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन संपन्न

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)

फैलता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण रायबरेली, इंश एड्स दिवस के संगठन (एनएसीओ) द्वारा जारी आंकड़ों का मानने को भारत में

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)

को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इस ग्रीमारी के प्रति समाज में फैली भ्रातियों को दूर करना और एड्स पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाना है। चिकित्सालय मैनेजर मण्डली उपाध्याय ने कहा जानकारी ही इसका बचाव है डॉ. मीरा अनंद, डॉ. सुजाता त्रिपाठी, सिस्टर शशीबाला सिंह, सरोजनी तिवारी (मैट्रन), आई०सी०टी०सी० काउसलर सीमा यादव, एल०टी० प्रभात शर्मा एवं चिकित्सालय के मैटिकल एवं पैरामैटिकल स्टॉफ उपस्थित रहे। ३०० मीरा एवं काउसलर सीमा यादव द्वारा स्टॉफ को एच० आई० वी० के बारे में जागरूक किया गया कि हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कैसे एच० आई० वी० से इलाज कर सकते हैं की देखभाल एवं इलाज कर सकते हैं एवं एच० आई० वी० गर्वती महिलाओं से जर्में बच्चों को हम सही समय पर इलाज देकर एच० आई० की विमारी से बचा सकते हैं।

रायबरेली में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय निर्माला कुमारी, एड्स एक संक्रमण की सी.एस.डॉ. डॉ. मीरा अनंद, एड्स एक संक्रमण की सी.एस.डॉ. एड्स को लेकर जागरूकता ही है, जिसके कारण इस घातक जानलेवा ग्रीमारी है, और इसके लिए लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। एड्स एक संक्रमण रोग है और यह महामारी की तरह एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों की संख्या में बीते 10 वर्षों में भारी कमी आई है। यह लोगों में एचआईवी/एड्स को लेकर जागरूकता ही है, जिसके कारण इस घातक जानलेवा ग्रीमारी को नियंत्रित किया जा सका है, और इसके लिए लोगों को बीच एचआईवी/एड्स महामारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयोक्त वर्ष १ दिसंबर बचा सकते हैं।

गोदौलिया से दशाश्वमेध तक होगा नो वैंडिंग जोन, जियो टैगिंग कराने का निर्णय

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क)

जाएगा। यह निर्णय बृद्धार को

वाराणसी। गोदौलिया से दशाश्वमेध क्षेत्र में लगने वाले जाम को देखते की बैठक में लिया गया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने फैरी पटरी का साथ मिलकर यह निर्णय लिया वालों से बाहर कि इस क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां संदर्भ पर कोई कारोबार नहीं करेगा। साथ ही यहां सड़कों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। अब फलाईज़ेर के नीचे स्ट्रीट फूड वैंडरों के लिए मॉडल स्ट्रीट फूड हब बनाया जाए। गोदौलिया से दशाश्वमेध क्षेत्र में यह भी तय हुआ कि पूर्व में जो वैंडिंग जोन के लिए सदस्यों से ही प्रस्ताव मांगे।

तत्वाधान में दयानन्द पी०जी० कॉलेज, बछारां, रायबरेली में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें शिवाशक्ति बायोटेकॉलॉजी लिं., बूसा मैनेजमेंट मार्कीटिंग लिं., पौपल ट्री ऑनलाइन, ब्राइट प्लूचर इंडिया प्र० लिं० द्वारा विभिन्न पदों हेतु उपस्थित प्रतिभागियों का साक्षात्कार किया गया जिसमें से 251 प्रतिभागियों को प्राथमिक रूप से विक्रेता (जीविका सुरक्षा एवं जैविक अन्यायों को पार्किंग कराई जाएगी। पथ क्षेत्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां संदर्भ पर कोई कारोबार नहीं करेगा। साथ ही यहां सड़कों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। अब वैंडिंग जोन के लिए सदस्यों से ही प्रस्ताव मांगे।

गयी। विद्यालय के प्राचार्य डॉ सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जिला सेवायोजन कार्यालय, रायबरेली एवं कम्पनी के प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। महाविद्यालय के डॉ अमित कुमार (रोजगार मेला प्रभारी), डॉ शिवकान्त शुक्ला, डॉ लवपाल सिंह, विजय कुमार, शिव प्रसाद, जितेन्द्र पाठक एवं जिला सेवायोजन कार्यालय, रायबरेली वैंडिंग जोन महायज्ञ में आहुति देने के लिए अमेरिका, कनाडा, नेपाल, स्टिटजरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, दुबई, दक्षिण अफ्रीका समेत 19 देशों के एक लाख से अधिक अन्यायों आहुतियों अंतिम वर्ष 2014 के तहत नवनिर्वाचित टाउन वैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने समस्या रखी। एहतिहासिक एवं अध्यर्थियों को रोजगार मेले के उद्देश्य एवं प्रासंगिकता

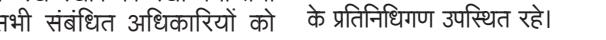
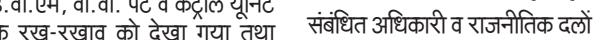
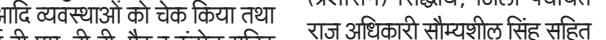
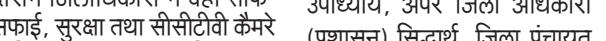
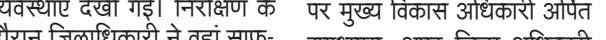
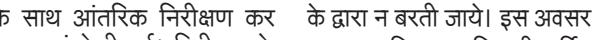
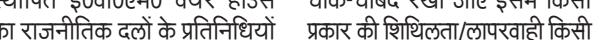
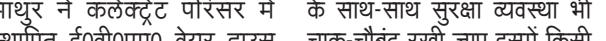
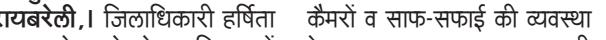
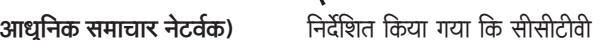
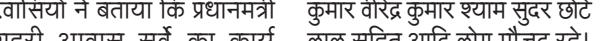
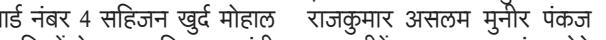
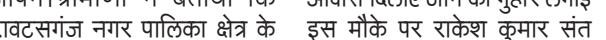
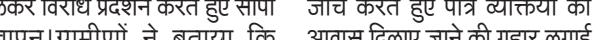
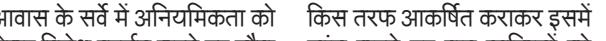
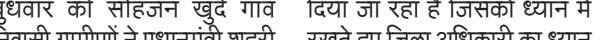
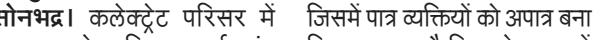
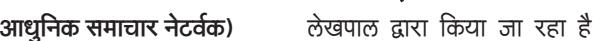
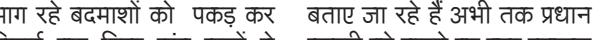
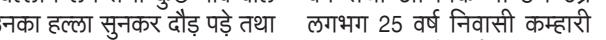
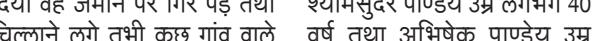
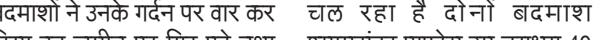
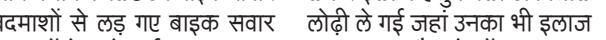
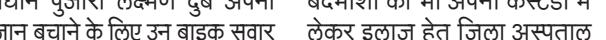
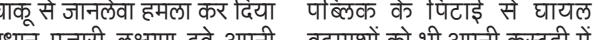
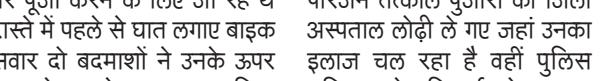
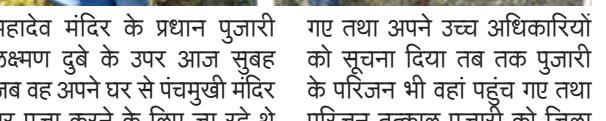
सहित कई राज्यों के अनुयायियों का जत्या महामंदिर धार्म पहुंचने लगा है। विंगम योग के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दूर-दूर से अनुयायियों ने नगर सज-धजकर तथा अंतिम वर्ष 2014 में अंतिम वर्ष 2015 में अंतिम वर्ष 2016 में अंतिम वर्ष 2017 में अंतिम वर्ष 2018 में अंतिम वर्ष 2019 में अंतिम वर्ष 2020 में अंतिम वर्ष 2021 में अंतिम वर्ष 2022 में अंतिम वर्ष 2023 में अंतिम वर्ष 2024 में अंतिम वर्ष 2025 में अंतिम वर्ष 2026 में अंतिम वर्ष 2027 में अंतिम वर्ष 2028 में अंतिम वर्ष 2029 में अंतिम वर्ष 2030 में अंतिम वर्ष 2031 में अंतिम वर्ष 2032 में अंतिम वर्ष 2033 में अंतिम वर्ष 2034 में अंतिम वर्ष 2035 में अंतिम वर्ष 2036 में अंतिम वर्ष 2037 में अंतिम वर्ष 2038 में अंतिम वर्ष 2039 में अंतिम वर्ष 2040 में अंतिम वर्ष 2041 में अंतिम वर्ष 2042 में अंतिम वर्ष 2043 में अंतिम वर्ष 2044 में अंतिम वर्ष 2045 में अंतिम वर्ष 2046 में अंतिम वर्ष 2047 में अंतिम वर्ष 2048 में अंतिम वर्ष 2049 में अंतिम वर्ष 2050 में अंतिम वर्ष 2051 में अंतिम वर्ष 2052 में अंतिम वर्ष 2053 में अंतिम वर्ष 2054 में अंतिम वर्ष 2055 में अंतिम वर्ष 2056 में अंतिम वर्ष 2057 में अंतिम वर्ष 2058 में अंतिम वर्ष 2059 में अंतिम वर्ष 2060 में अंतिम वर्ष 2061 में अंतिम वर्ष 2062 में अंतिम वर्ष 2063 में अंतिम वर्ष 2064 में अंतिम वर्ष 2065 में अंतिम वर्ष 2066 में अंतिम वर्ष 2067 में अंतिम वर्ष 2068 में अंतिम वर्ष 2069 में अंतिम वर्ष 2070 में अंतिम वर्ष 2071 में अंतिम वर्ष 2072 में अंतिम वर्ष 2073 में अंतिम वर्ष 2074 में अंतिम वर्ष 2075 में अंतिम वर्ष 2076 में अंतिम वर्ष 2077 में अंतिम वर्ष 2078 में अंतिम वर्ष 2079 में अंतिम वर्ष 2080 में अंतिम वर्ष 2081 में अंतिम वर्ष 2082 में अंतिम वर्ष 2083 में अंतिम वर्ष 2084 में अंतिम वर्ष 2085 में अंतिम वर्ष 2086 में अंतिम वर्ष 2087 में अंतिम वर्ष 2088 में अंतिम वर्ष 2089 में अंतिम वर्ष 2090 में अंतिम वर्ष 2091 में अंतिम वर्ष 2092 में अंतिम वर्ष 2093 में अंतिम वर्ष 2094 में अंतिम वर्ष 2095 में अंतिम वर्ष 2096 में अंतिम वर्ष 2097 में अंतिम वर्ष 2098 में अंतिम वर्ष 2099 में अंतिम वर्ष 2100 में अंतिम वर्ष 2101 में अंतिम वर्ष 2102 में अंतिम वर्ष 2103 में अंतिम वर्ष 2104 में अंतिम वर्ष 2105 में अंतिम वर्ष 2106 में अंतिम वर्ष 2107 में अंतिम वर्ष 2108 में अंतिम वर्ष 2109 में अंतिम वर्ष 2110 में अंतिम वर्ष 2111 में अंतिम वर्ष 2112 में अंतिम वर्ष 2113 में अंतिम वर्ष 2114 में अंतिम वर्ष 2115 में अंतिम वर्ष 2116 में अंतिम वर्ष 2117 में अंतिम वर्ष 2118 में अंतिम वर्ष 2119 में अंतिम वर्ष 2120 में अंतिम वर्ष 2121 में अंतिम वर्ष 2122 में अंतिम वर्ष 2123 में अंतिम वर्ष 2124 में अंतिम वर्ष 2125 में अंतिम वर्ष 2126 में अंतिम वर्ष 2127 में अंतिम वर्ष 2128 में अंतिम वर्ष 2129 में अंतिम वर्ष 2130 में अंतिम वर्ष 2131 में अंतिम वर्ष 2132 में अंतिम वर्ष 2133 में अंतिम वर्ष 2134 में अंतिम वर्ष 2135 में अंतिम वर्ष 2136 में अंतिम वर्ष 2137 में अंतिम वर्ष 2138 में अंतिम वर्ष 2139 में अंतिम वर्ष 2140 में अंतिम वर्ष 2141 में अंतिम वर्ष 2142 में अंतिम वर्ष 2143 में अंतिम वर्ष 2144 में अंतिम वर्ष 2145 में अंतिम वर्ष 2146 में अंतिम वर्ष 2147 में अंतिम वर्ष 2148 में अंतिम वर्ष 2149 में अंतिम वर्ष 2150 में अंतिम वर्ष 2151 में अंतिम वर्ष 2152 में अंतिम वर्ष 2153 में अंतिम वर्ष 2154 में अंतिम वर्ष 2155 में अंतिम वर्ष 2156 में अंतिम वर्ष 2157 में अंतिम वर्ष 2158 में अंतिम वर्ष 2159 में अंतिम वर्ष 2160 में अंतिम वर्ष 2161 में अंतिम वर्ष 2162 में अंतिम वर्ष 2163 में अंतिम वर्ष 2164 में अंतिम वर्ष 2165 में अंतिम वर्ष 2166 में अंतिम वर्ष 2167 में अंतिम वर्ष 2168 में अंतिम वर्ष 2169 में अंतिम वर्ष 2170 में अंतिम वर्ष 2171 में अंतिम वर्ष 2172 में अंतिम वर्ष 2173 में अंतिम वर्ष 2174 में अंतिम वर्ष 2175 में अंतिम वर्ष 2176 में अंतिम वर्ष 2177 में अंतिम वर्ष 2178 में अंतिम वर्ष 2179 में अंतिम वर्ष 2180 में अंतिम वर्ष 2181 में अंतिम वर्ष 2182 में अंतिम वर्ष 2183 में अंतिम वर्ष 2184 में अंतिम वर्ष 2185 में अंतिम वर्ष 2186 में अंतिम वर्ष 2187 में अंतिम वर्ष 2188 में अंतिम वर्ष 2189 में अंतिम वर्ष 2190 में अंतिम वर्ष 2191 में अंतिम वर्ष 2192 में अंतिम वर्ष 2193 में अंतिम वर्ष 2194 में अंतिम वर्ष 2195 में अंतिम वर्ष 2196 में अंतिम वर्ष 2197 में



गाइक सवार बदमाशों ने जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल सांसद प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोकना निदनीयःराघवेंद्र नारायण पर जानलेवा हमला

(आधुनिक समाचार नेटर्वर्क) हवाले कर दिया सूचना पर चौकी प्रभारी चुकू सुनील कुमार अपने सहिंजन खुर्द स्थिति पंचमुखी

चुकू सोनभद्र। चौकी क्षेत्र अंतर्गत हमराहिंगो के साथ मौके पर पहुंचा



सम्पादकीय

**कब रुकेगी मानवता को
शर्मसार करने वाली घटनाएं**

द्वारा भारत को जादू-टोने का देश तक बता दिया जाता था, लेकिन पिछले सात दशक में हमने न केवल तरकी की ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) जैसे क्षेत्रों में दुनिया को राह दिखा रहे हैं। भोपा या जादू-टोना करने वाले केवल पिछड़े या ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं हैं। इनकी जड़े दिल्ली समेत अधिकांश शहरों में जमी हुई हैं। बड़े-बड़े शहरों के चौराहों पर अक्सर आपको ऐसे कार्ड बांटने वाले मिल जाएंगे, जो वशीकरण, मनवाहा प्यार, गृह कलेश, जादू-टोना, पति-पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं। जब कोई व्यक्ति चारों ओर से निराश होता है तो इन जादू-टोटका करने वालों के फेर में आ जाता है। बस यही पर किसी भी व्यक्ति के दैर्घ्य और सोच-समझ की परीक्षा होती है। हमें ये समझना चाहिए कि यदि कोई बीमार है या जीवन में परेशानी है तो उसका इलाज डॉक्टर या वैद्य के पास मिलेगा। कई बार हम डॉक्टर से इलाज कराते-कराते उस स्थिति में इलाज का छोड़ देते हैं, जब बीमारी ठीक होने वाली होती है। फिर जादू टोटका करने वालों के फेर में आ जाते हैं और दो-चार लोगों को राहत मिलती है तो वो इनका मुफ्त में प्रचार करने लग जाते हैं। ऐसे फर्जी लोग केवल अपने ठिकाने बनाकर नहीं बैठे हैं, बल्कि बाकायदा खुले मंच सजाकर भी बीमारियां ठीक करने का स्वांग रखते हैं। ऐसे सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। डायन प्रथा को लेकर कोई केंद्रीय कानून तो नहीं है, लेकिन राज्यों में अपने-अपने यहां कानून बना रखे हैं। राजस्थान डायन प्रताइना निवारण अधिनियम 2015 और राजस्थान डायन प्रताइना निवारण नियम 2016 के तहत किसी महिला को डायन घोषित कर बदनाम या प्रताइत कर नुकसान पहुंचाने पर अपराधी को 1 से 5 साल तक कठोर कारावास या 50,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्ञाह-फूंक, तंत्र-मंत्र, जादू-टोटका कर किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाता है तो उसे 1 से 3 साल तक का कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। वैसे तो शासन-प्रशासन डायन प्रथा को लेकर समय-समय पर जन-जागरूकता के कार्यक्रम चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर खुलेआम फर्जी दावे कर रहे तत्वों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। सरकारी बसों में ऐसे स्टिकर लगे मिल जाते हैं, जो वशीकरण, बीमारियों का शर्तिया इलाज आदि का दावा करते हैं।



म वस्त्रार स जानत ह किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर तीसरी बार देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली कूच के पहले ही आंदोलनकारी किसान संगठनों में फूट पड़ गई है। उधर केन्द्र व भाजपाशास्त्रित राज्य सरकारें किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित मानकर खारिज करती रही हैं तो किसानों का मानना है कि सरकार उनकी मांगों को मानना ही नहीं चाहती। देश की राजधानी में तीसरी बार हो रहे, इस किसान आंदोलन के औचित्य को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हाल में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप थनकड़ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री से जवाब तलब कर नई सनसनी फैला दी कि किसानों की मांगों को लेकर आखिर सरकार कर क्या रही है? मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान संकट में है और आंदोलन कर रहे हैं। यह स्थिति तत्व ह, इस समझन क साथ साथ इस बात का विश्लेषण भी जरूरी है कि किसान जो मांगें लगातार करते आ रहे हैं, उनका स्थायीकरण करना कारक हल क्यों नहीं होता है और यह भी क्या इस तरह तकरीबन हर साल किसानों का आंदोलन करना सुनियोजित एंडब्ल्यूए का हिस्सा बन चुका है देश में किसान आंदोलन की शुरुआत 2020 में कोरोना प्रकोप के दौरान ही मोदी सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों के विरोध में हुई थी। यह देश में अब तक का सबसे लंबा चला आंदोलन था। नतीजे यह हुआ कि मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। हालांकि सरकार का एक कदम पीछे खींचना राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि इसने कृषि कानून विरोधी आंदोलनों की धार को ही कुंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। देश में किसान आंदोलन की शुरुआत 2020 में कोरोना प्रकोप के दौरान ही मोदी सरकार द्वारा लागू तीन

कायदमद हा साबत हुआ, क्योंकि इसने कृषि कानून विरोधी आंदोलन की धार को ही कुंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। दरअसल, किसानों की जायज समस्याएं और उनका निदान ऐसे आंदोलनों तथा उस पर होने वाली राजनीति के धूध में खो जाता है। किसानों का हफ्तों धरने पर बैठना, रास्ते रोकना, आंदोलन का किसानों की आंतरिक राजनीति का शिकार होना, सत्तापक्ष और विपक्षी सरकारों द्वारा इसका ट्रॉटमेंट अपने अपने राजनीतिक हितों के नजरिए से करना, एक आम और गरीब किसान का ऐसे आंदोलनों से दूर ही रहना, प्रशासन द्वारा आंदोलनकारी किसानों से कभी नरमी तो कभी सख्ती से निपटना, केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह के आंदोलन को प्रायोजित मानकर इसकी उपेक्षा करना, इन किसान आंदोलन के स्थायी बिंदु बन चके हैं। सवाल यह भी उठते रहे हैं कि खेती के मौसम में किसान इतनी लंबी अवधि तक धरने पर कैसे बैठे रह सकते हैं? किसान नहा है? इसके साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि किसान को लगातार मुश्किल में डालकर सरकार आर्थिकी को बुलेट की रफतार से आगे कैसे ले जाएगी ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों की कोई मांग नहीं मानी हो, लेकिन देश में किसी एक वर्ग को ही सर्वस्व मानकर उसे संतुष्ट करने की राह पर तो कोई सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। इस समूची व्यवस्था का किसान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, इससे इंकार नहीं, लेकिन किसान और वो साधन सम्बन्ध किसान ही सब कुछ हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन अपने ही अंतर्विरोधों का शिकार ज्यादा हो गया है। इस बार भी 40 किसानों के छाता संगठन संयुक्त किसान मोर्चे (एसकेएम) ने किसान आंदोलन से दूरी बना ली है। उसका कहना है कि जो कुछ हो रहा है, इसमें उनकी राय नहीं ली गई है। इसी तरह किसान नेता राकेश टिकैत भी इस आंदोलन से दूर है। हरियाणा के किसान संगठनों ने किसानों को इस आंदोलन को आधिक नहा है? मादा सरकार आर भाजपा आंदोलन की इस कमज़ोरी से वाकिफ हैं। यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जो किसान धूप, बारिश और सर्दी में भी डटकर आंदोलन में खड़ा होता है, चुनावी राजनीति में उसका व्यवहार कुछ और होता है। मसलन तीन कृषि कानून वापसी के पीछे भाजपा का यह भय था कि इसका असर 2022 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव पर न पड़े। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें शामिल थे। लेकिन चुनाव नतीजे में भाजपा फिर सत्ता में लौट आई। सबसे हैरान करने वाला परिणाम तो पंजाब विधानसभा चुनाव का था, जहां किसानों के संगठन संयुक्त समाज मोर्चा ने 104 प्रत्याशी चुनाव में खड़े किए, लेकिन इनमें कोई भी जमानत भी नहीं बचा पाया। यह मोर्चा भी किसान आंदोलन में सक्रिय था हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे ने चुनाव से दूरी बना ली थी। हाल में हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने भी यही साबित किया। बाकी राज्यों के किसानों की इस आंदोलन में भागीदारी नहीं के बराबर है, जबकि हाँ का मादा सरकार किसानों का मांगों को केवल राजनीतिक चश्में से देखती है या फिर उन्हें लगा कि किसानों की जायज मांगों के हल के लिए कोई ठोस उपाय अभी भी नहीं किए गए हैं उपराष्ट्रपति की पीड़ा इसलिए भी विजिब है, क्योंकि उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना। यह भी संभव है कि वो सरकार पर दबाव बनाना चाहते हों कि उन्हें इसी पद पर दूसरा कार्यकाल मिले। लेकिन इससे यह सवाल डायलूट नहीं होता कि किसान आंदोलन पूरी तरह प्रायोजित है और इसका एक मात्र मकसद सरकार को छूकेमेल करते रहना है। उपराष्ट्रपति के कहने का आशय यही है कि सरकार किसान संगठनों से बात तो करे। संवाद से ही कुछ समाधान निकलने की संभावना है। इस बीच यूपी सरकार ने किसानों के मुद्दे के निराकरण के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी है। समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान के सामने भी चुनौती है कि वो किसानों की समस्या का निदान कैसे करते हैं? कर भी पाते हैं या नहीं।

किसानों को बार-बार दिल्ली कूच क्यों करना पड़ता है

सरकार आर किसाना के बाच लगातार खाई बढ़ती जा रही है। उपराष्ट्रपति ने भी किसानों की समस्या पर चिंता जताई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किसानों को बार-बार दिल्ली क्यों कूच दश के लिए अच्छा नहीं हा। सरकार को आत्मावलोकन की जरूरत है। क्या किसानों से कोई गादा किया गया था? क्या वह पूरा नहीं हुआ? इसी कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान भी मौजूद थे।

हे? उनके आदालत का हस्ता बनने पर खेती का काम कौन संभालता है आंदोलन के चलते अगर खेती पर ध्यान न दिया तो उससे होने वाला नुकसान एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदी नहीं होने भा अपने हाथ खाच लिए ह। हालांकि इस बार भी किसानों की मुख्य मांग फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की है। आंदोलनकारी किसानों की एक बड़ी समस्या, इस आंदोलन की ताकत समग्रता में देख तो दश में किसानों की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की समस्या का मुद्दा उठाकर केन्द्र सरकार को कठघरे

से होने वाली हानि की तुलना में अधिक नहीं है? इसी के साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि किसानों को लगातार मुश्किल में डालकर सरकार आर्थिकी को बुलेट की रफतार से आगे कैसे ले जाएगी ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों की कोई मांग नहीं मानी हो, लेकिन देश में किसी एक वर्ग को ही सर्वस्व मानकर उसे संतुष्ट करने की राह पर तो कोई सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। इस समूची व्यवस्था का किसान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, इससे इंकार नहीं, लेकिन किसान और वो साधन सम्पन्न किसान ही सब कुछ हों, ऐसा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन अपने ही अंतर्विरोधों का शिकार ज्यादा हो गया है। इस बार भी 40 किसानों के छाता संगठन संयुक्त किसान मोर्च (एसकेएम) ने किसान आंदोलन से दूरी बना ली है। उसका कहना है कि जो कुछ हो रहा है, इसमें उनकी राय नहीं ली गई है। इसी तरह किसान नेता राकेश टिकैत भी इस आंदोलन से दूर है। हरियाणा के किसान संगठनों ने

का राजनीतिक रूपांतरण न होने की है। मोदी सरकार और भाजपा आंदोलन की इस कमज़ोरी से वाकिफ़ हैं। यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जो किसान धूप, बारिश और सर्दी में भी डटकर आंदोलन में खड़ा होता है, चुनावी राजनीति में उसका व्यवहार कुछ और होता है। मसलन तीन कृषि कानून वापसी के पीछे भाजपा का यह भय था कि इसका असर 2022 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव पर न पहੁँचे। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें शामिल थे। लेकिन चुनाव नतीजे में भाजपा फिर सत्ता में लौट आई। सबसे हैरान करने वाला परिणाम तो पंजाब विधानसभा चुनाव का था, जहां किसानों के सगठन संयुक्त समाज मोर्चा ने 104 प्रत्याशी चुनाव में खड़े किए, लेकिन इनमें कोई भी जमानत भी नहीं बचा पाया। यह मोर्चा भी किसान आंदोलन में सक्रिय था हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे ने चुनाव से दूरी बना ली थी। हाल में हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने भी यही साबित किया। बाकी राज्यों के किसानों की इस आंदोलन में भागीदारी नहीं के बराबर है, जबकि

में खड़ा क्यों किया? क्या उन्हें लगता है कि मोदी सरकार किसानों की मांगों को केवल राजनीतिक चश्में से देखती है या फिर उन्हें लगा कि किसानों की जायज मांगों के हल के लिए कोई ठोस उपाय अभी भी नहीं किए गए हैं उपराष्ट्रपति की पीड़ा इसलिए भी वाजिब है, क्योंकि उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना। यह भी संभव है कि वो सरकार पर दबाव बनाना चाहते हों कि उन्हें इसी पद पर दूसरा कार्यकाल मिले। लेकिन इससे यह सवाल ढायल्यूट नहीं होता कि किसान आंदोलन पूरी तरह प्रायोजित है और इसका एक मात्र मकसद सरकार को लैंकेमेल करते रहना है। उपराष्ट्रपति के कहने का आशय यही है कि सरकार किसान संगठनों से बात तो करे। संवाद से ही कुछ समाधान निकलने की संभावना है। इस बीच यूपी सरकार ने किसानों के मुद्दे के निराकरण के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी है। समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान के सामने भी चुनौती है कि वो किसानों की समस्या का निदान कैसे करते हैं? कर भी पाते हैं या नहीं?

गरोब कौदेयो को जमानत ना मिल पाना भी अन्याय, आखेर कब मिलेगा न्याय

मिलनात मिलना एक बहुत मुश्किल है और जटिल प्रक्रिया है, जबकि अमीर आरोपी जल्दी रिहा हो जाते हैं। सरकार ने गरीब कैंदियों की विदद के लिए योजना बनाई है लेकिन यजमानी स्तर पर स्थिति ज्यांची की चेहरों हैं। न्याय किसी भी शासन यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है और समानता उस न्याय व्यवस्था का एक मौलिक आधार है। अगर न्यायिक व्यवस्था में अमीर गरीब के भेद की गुजांइश हो तो वह यवस्था न केवल अपूर्ण होती है वित्तिक न्याय के बजाय अन्याय को दिखाती जन्म देती है जिसका परिणाम असन्तोष और अराजकता के रूप में सामने आ सकता है। विष्वात्-फेलम अभिनेता सलमान खान को 7 अप्रैल 2018 को जोधपुर की जिला वर्धन सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत मंजूर होने पर मात्र कुछ सीधांठों में जेल से रिहा कर दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर सेंटर वॉर रिसर्च एंड प्लानिंग (सीआरपी) ने एक रिपोर्ट के अनुसार-

किए जाने पर इसी महीने हैरानी जताई है। इससे पहले भी सर्वोच्च अदालत 2023 और 2021 में इस मुद्दे पर चिन्ता जाने के साथ ही की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी के आधार पर विचाराधीन कैदियों के लिए 40,000 रुपये और दोषियों के लिए 25,000

लागू करने को कहा था। लेकिन बावजूद इन प्रयासों के अदालत से जमानत मिलने पर भी बड़ी संख्या में गरीब केंद्रियों का जेल से न छुट

शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। जबकि आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक जेलों में पढ़े रहते हैं। न्याय भी अक्सर महंगे और सस्ते तथा सुलभ है कि न्याय का सिद्धान्त तब तक किसी आरोपी को निर्दोष मानता है जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए। सन् 2023 की एक सरकारी रिपोर्ट थे जिनमें से 11,490 कैदी अदालत से जमानत मिलने पर भी जेलों में निरुद्ध थे। इन विचाराधीन बंदियों में 382 महलाएं भी थीं। इन विचाराधीन बंदियों में 1,07,946



मुगत रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट 2019 के एक फैसले में कह चुका है कि जमानत राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में कैदियों को जेल में रखना अवैध और कैदी के संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अभ्य ओका और जी. मसीह की सुप्रीम कोर्ट की

रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। योजना को लागू करने के लिए 23 मई 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्य मंत्रियों को और फिर 23 अक्टूबर 2023 को गृह मंत्रालय के उपसचिव अरुण सोब्ही ने सभी राज्यों के गृह सचिवों

पाना हमारी अपराधिक न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ही है। कहां है निष्पक्षता और समानता भारत की न्याय प्रणाली निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। मगर व्यवहार में यह प्रणाली उन लोगों को प्राथमिकता

वकीलों पर निर्भर करता है, इसलिए समाज में कई अहंकारी आज भी न्याय खरीदने का दंभ भरते हैं। फैसले तक आरोपी निर्दोष माना जाता है देखा जाए तो जमानत का उद्देश्य अभियुक्त के अधिकारों और अदालत में उनकी उपस्थिति

के अनुसार उस समय भारत की जेलों में 5,73,000 से अधिक कैदियों में 75 प्रतिशत से अधिक ऐसे विचाराधीन हैं जिन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम् जेल साख्यकी के अनुसार 31 विचाराधीन केंदी लखे समय बाद जेल से छुट तो जाते हैं लेकिन वे घर पहुंचते हैं तो उनके साथ असाध्य रोग भी होते हैं। नहीं मिल रहा कल्याणकारी कानूनों का लाभ गरीब कैदियों की लंबे समय तक हिरासत को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं लेकिन उनका असमानताओं की याद दिलाती है। यह नीति-निर्माताओं, कानूनी पेशेवरों और नागरिक समाज के लिए एक जुट होकर एक अधिक समावेश और न्यायसंगत् प्रणाली बनाने का आह्वान है। सच्चा न्याय तभी संभव है जब हर व्यक्ति, चाहे उसका आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अपना

ADHUNIK TUTORIALS

" FOR THE STUDENTS, FROM A STUDENT "

FOR CLASSES 1ST 5TH
(ADMISSION OPEN)

FACILITIES

- **Air Conditioned & Well Furnished Classroom**
 - **Water Cooler Available**
 - **Hygienic Washrooms**
 - **CCTV for Safety Purposes**
 - **In Campus Parking**



Dr. (Er)PuneetArora (HON. DIRECTOR)

(B.Tech, M.Tech, MBA, Ph.D)
with IITian Scientist & Past

**Awarded with Young Scientist & Best
Teachers, Author of Many Books
Chapters, Research Paper,
Patent & Trademarks**



Ms.Nitanjana Arora (Assistant Director)

- Ex. Student of Bethany Convent School, Bishop Johnson School & College, Girl's High School & College
 - Pursuing B.Tech
 - Awarded by TCS
 - Certification in the Field of Web Development and Machine Learning .

Ms. Riya Hirata (Co-Coordinator)

- Subject Topper of Delhi Public School
 - Pursuing LLB from University of Allahabad .



Contact :- Call and Whatsapp: 8542919234

काट्स के डॉक्टरों ने दुलन विकार से पांडा ३९-वर्षीय महिला की हाइ-रिस्क रीनल ट्यूमर एक्स्ट्रेक्शन सर्जरी की (आधुनिक समाचार नेटर्वर्क) नोट्टा। नोट्टा फोर्टिस हॉस्पीटल नोट्टा के डॉक्टरों ने मल्टीपल वास्क्युलर एनोमलीज़ से पीड़ित ५९ वर्षीय एक महिला मरीज की हाइ-रिस्क सर्जरी कर रीनल ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला। मरीज जन्मजात विकार मल्टी पल वास्क्युलर एनोमलीज़ से ग्रस्त थीं जिसमें अनेक असामान्य रक्त वाहिकाएं गुर्दों को रक्तपूर्ति करती हैं, यह विकार २५००० में से १ व्यक्ति में ही देखा गया है। सामान्य तौर पर, एक गुर्दे में केवल एक धमनी (आर्टरी), एक शिरा (वेन) और एक मूत्रवाहिका (यूरेटर) होती है, लेकिन इस मामले में, मरीज के शरीर में ४ रीनल आर्टरी और २ यूरेटर थे। उनके बाएं गुर्दे के निचले भाग से ट्यूमर को निकालना और इससे पहले वहां मौजूद कई धमनियों और शिराओं को बांधना काफी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन डॉ पीष्य वार्ष्य - डायरेक्टर, यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस हॉस्पीटल, नोट्टा के नेतृत्व में अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने इस हाइ-रिस्क

स्थिर अवस्था में अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। मरीज को शरीर के बाएं भाग में काफी तेज दर्द की शिकायत के साथ फोर्टिस नोट्टा में भर्ती किया गया था, उहैं पसिलियों से लेकर कूल्हों तक में दर्द था। मरीज का अल्ट्रासाउंड किया गया जिससे उनके बाएं गुर्दे के निचले भाग में एक ट्यूमर का पता चला। इसके अलावा, मरीज की सी.टी. यूरोग्राफी भी की गई जिससे उनके गुर्दे को रक्तपूर्ति करने वाली अनेक असामान्य धमनियों और शिराओं का पता चला। इस कंडीशन के चलते, उनकी रक्तवाहिकाओं को काटने, उहैं अलग-अलग कर ट्यूमर को बाहर निकालने पर काफी अधिक लीडिंग होने का खतरा था। इस जटिल समस्या के समाधान के तौर पर डॉक्टरों की टीम ने रोबोट-एसिस्टेड पार्श्वियल नेफ्रेक्टोमी करने का फैसला किया, जिसने रक्तवाहिकाओं को १० गुना बड़ा करके दिखाया और डॉक्टरों के लिए इहें सावधानीपूर्वक कांट-छांटकर ट्यूमर को निकालना आसान हो गया। मामले की नोट्टा ने कहा, इस मामले की जटिलता के महेनज़र यह काफी चुनौतीपूर्ण सर्जरी थी, हमें गुर्दे को रक्तपूर्ति कर रही सभी प्रमुख धमनियों की पहचान कर उन्हें बिना क्षति पहुंचाएं काटना था, हरेक धमनी और शिरा को अलग-अलग कर बांधना था ताकि बिना खून बहाए किडनी ट्यूमर को हटाया जा सके। रोबोट की सहायता से पार्श्वियल (आंशिक) नेफ्रेक्टोमी कर, हमने ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला और इस प्रक्रिया में आसपास के टिश्यू या रक्तवाहिकाओं को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यदि इस ट्यूमर को समय पर नहीं निकाला जाता तो यह किसी भी समय फट सकता था और उस स्थिति में काफी अधिक लीडिंग होती। इस तरह के ट्यूमर के साथ एक समस्या यह होती है कि ये चर्बी और रक्तवाहिकाओं से बने होते हैं और इनके ऊपर से किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं होता। इस वजह से, कई बार एक मामूली चोट से ही यह फट सकते हैं और एक चोट से ही

एसएसपी ने तीन पुलिसकर्मियों को किया निलंबित (आधुनिक समाचार नेटवर्क) वाराणसी। रअसल, गीडा इलाके के अमटौरा गांव में मंगलवर को साइकिल हटाने को लेकर विवाद में पड़ोस में रहने वाले आरोपियों ने शिवधनी निषाद (55) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद घर के बाहर लगे छपर में आग लगाकर मनबद्ध फरार हो गए। इस घटना में लापरवाही मानते हुए एसएसपी ने एक दरोगा व दो आरक्षी के निलंबित कर दिया। गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा गांव में शिवधनी हत्याकांड मामले में तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। एसएसपी डॉ गौखर ग्रोवर ने लापरवाही बरतने पर गीडा थाने में तैनात दरोगा अजय राज यादव, आरक्षी जितेंद्र यादव और आशीष वर्मा को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सूत्रों की मानें को पहले दिन विवाद के बाद अगर पुलिस ने सख्त

सयुक्त किसान मजदूर संगठन को राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पाडत को आगरा टोल पर गिरफ्तार करने के संबंध में ज्ञापन (आधिकारिक समाचार ट्रेटर्क) मनिस्ट्रेट कार्यालय सेक्टर 19, किसानों द्वारा महामांगायत की गई के लिए उचित उपाय किया जाएं।

A photograph showing a group of approximately 20-25 individuals gathered outside a building. The group is diverse in age and gender, with many wearing green caps and scarves, suggesting they are part of a specific organization or movement. They are standing in two main groups: one on the left and a larger one on the right. In the foreground, several police officers in uniform are visible, some facing the group and others looking towards the camera. The building behind them has a sign that appears to read "नव योगी सेवा". The scene suggests a formal gathering or protest taking place in a public space.

किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्याना बुलंदशहर पूनम पंडित को बिना मौहला पुलिस के आगरा टोल पर गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तारी के विरोध में आज दिनांक 5.12.2024 को समय 12 बजे तक जारी रखी गई है।

को ज्ञापन दिया। जनपद-गौतमबुद्धनगर के किसानों द्वारा शांति पूर्वक दलित प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था पुलिस प्रशासन द्वारा शासन स्तर से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया था फिर भी अगले दिन दिनांक 2.12.2024 को 12 बजे

किया गया यह संविधान का उल्लंघन है उसी सन्दर्भ में संयुक्त किसान मजदूर संगठन अन्तर्राष्ट्रीय शूटर किसान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित जी को बिना महिला पुलिस द्वारा आगरा टोल पर गिरफ्तार किया गया है यह संविधान की खुले आंखें खोल दी गई हैं।

